

बढ़ते करज़ से घरेलू बचत पर संकट

प्रलिस के लयि:

[घरेलू उपभोग वयय सर्वेक्षण](#), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, [सकल घरेलू उत्पाद](#), [उपभोक्ता मूल्य मुद्रासफीति](#), [नीतिआयोग](#), मासकि प्रतति व्यक्त उपभोक्ता वयय, सी. रंगराजन समति।

मेन्स के लयि:

हाल के घरेलू उपभोग वयय सर्वेक्षण की मुख्य बातें

स्रोत: द हदि

हाल ही में [सकल घरेलू उत्पाद अनुपात](#) के मुकाबले अधिक ऋण लेने के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान [सकल घरेलू उत्पाद \(Gross Domestic Product - GDP\)](#) अनुपात की तुलना में घरेलू नविल बचत में आई गरावट के मुद्दे पर बहस शुरू हुई है।

- भारत सरकार के **मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA)** ने इसकी व्याख्या **घरेलू बचत की संरचना में बदलाव मात्र** के रूप में की, जहाँ परिवारों को केवल उच्च भौतिक बचत (नविश) के वतिपोषण के लयि अधिक ऋण लेना पड़ता है।
- हालाँकि, कुछ **वशिषज असहमत** हैं और उनका मानना है कि इस प्रवृत्ति के पीछे केवल लोगों की अत्यधिक खर्च करने की आदतें ही नहीं, बल्कि कई बड़े आर्थिक कारण भी हो सकते हैं।

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA):

- ये सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं और भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पूर्वसंसद में पेश कयि जाने वाले भारत के **आर्थिक सर्वेक्षण** की तैयारी के लयि ज़िमेदार होते हैं।
- CEA भारत सरकार के वति मंत्रालय के **आर्थिक मामलों के वभाग के आर्थिक प्रभाग** का प्रमुख होता है।
- उसके पास भारत सरकार के **सचवि** का पद होता है।

नोट:

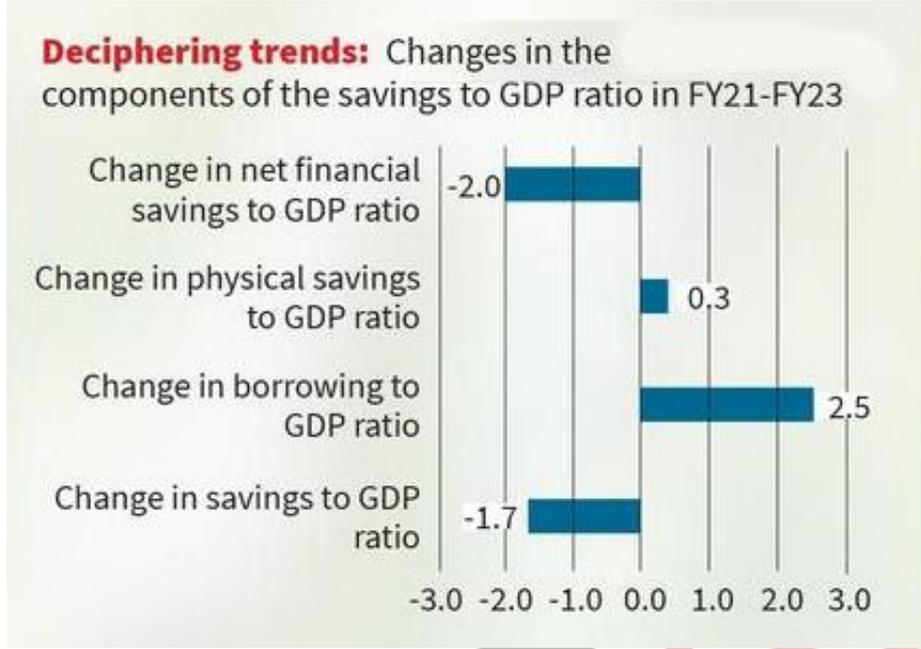
- घरेलू शुद्ध वतितीय बचत:** यह **घरेलू आय के उस भाग** को संदर्भति करता है जो ऋण एवं **वतितीय देनदारियों के बाद** बचता है तथा वतितीय परसंपत्तियों, जैसे बैंक जमा, स्टॉक, बॉण्ड तथा अन्य वतितीय उपकरणों में **नविश** कयि जाता है।
 - यह एक अवधि में परिवारों द्वारा रखी गई **वतितीय संपत्तियों में शुद्ध परिवर्तन** का प्रतनिधित्व करता है।
 - उच्च शुद्ध वतितीय बचत उच्च आर्थिक स्थरिता का संकेत देती है।
- घरेलू बचत और GDP अनुपात:** **घरेलू बचत और GDP का अनुपात** इसकी **शुद्ध वतितीय बचत** एवं GDP अनुपात, **भौतिक बचत** तथा GDP अनुपात व **सोने और आभूषणों** का योग है।
 - गणतीय अभविक्रत रूप में:** घरेलू बचत = शुद्ध वतितीय बचत + भौतिक बचत + (स्वर्ण और आभूषण)।

बचत पैटर्न में वर्तमान परिवर्तन क्या हैं?

- बढ़ा हुआ उधार और संपत्ति में स्थरिता:**
 - अधिक उधारी (2.5% तक) होने से **शुद्ध वतितीय बचत (-2.0% तक)** कम हो गई है, लेकिन भौतिक बचत तथा नविश में अधिक वृद्धि (केवल 0.3% तक) नहीं हुई है।
 - यह सरकार के उस **दृष्टिकोण का खंडन** करता है कि अधिक उधार लेने (शुद्ध वतितीय बचत में कमी) के कारण भौतिक बचत में

वृद्धि हुई है।

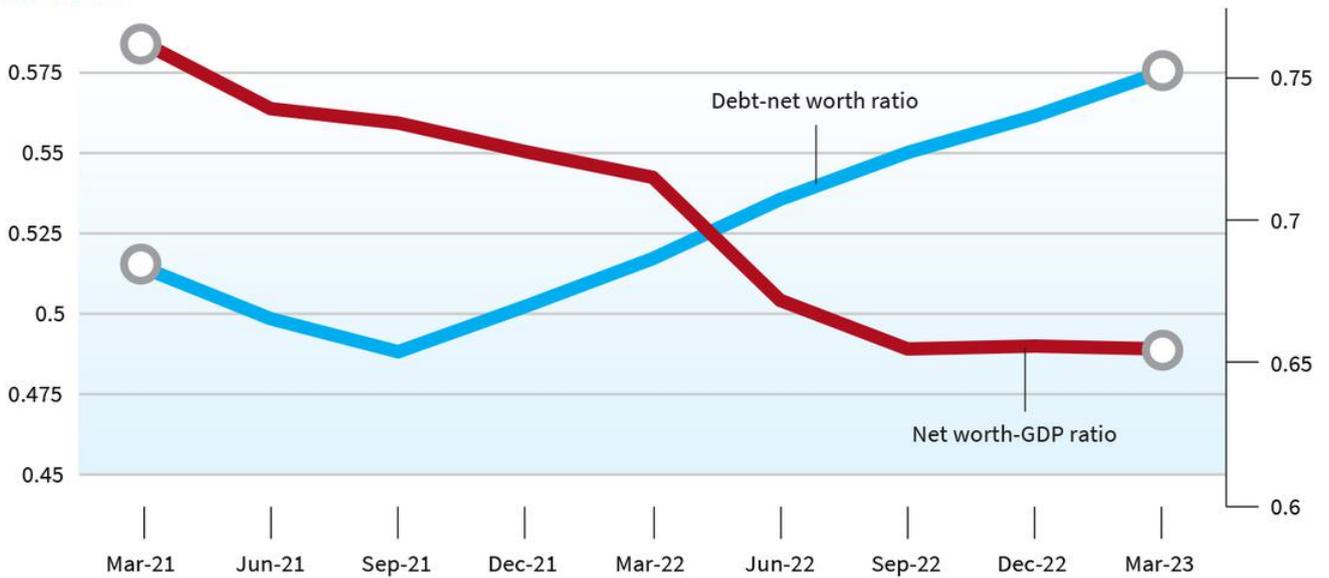
- घरेलू बचत और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 1.7% अंक की गिरावट आई, जबकि सोने की बचत व सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात काफी हद तक अपरिवर्तित रहा।



■ घरेलू वित्तीय संपत्ति और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गिरावट:

- समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में परिवार नरिधन होते जा रहे हैं, साथ ही अधिक धन भी उधार ले रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू वित्तीय संपत्ति और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात तेज़ी से कम हुआ है, जबकि ऋण-से-नविल-मूल्य अनुपात बढ़ गया है।

Figure 4: Household net worth GDP ratio and debt-net worth ratio



■ ब्याज भुगतान बोझ, किसी नरिधारति ब्याज दर पर, ब्याज दर और ऋण-आय (DTI) के अनुपात का उत्पाद है।

- ब्याज भुगतान बोझ में वृद्धि: ब्याज भुगतान का बोझ किसी नरिधारति ब्याज दर पर, ब्याज दर और ऋण-आय (DTI) के अनुपात का उत्पाद है।
- ऋण-से-आय (Debt-To-Income- DTI) अनुपात एक वित्तीय अनुपात है जो उधारकर्ता के कुल मासिक ऋण की तुलना

उनकी कुल मासिक आय से करता है।

- उच्च ऋण-से-आय अनुपात इंगति करता है कि किसी व्यक्ति को अपने ऋणों पर चूक का जोखिम हो सकता है, जबकि निम्न अनुपात दर्शाता है कि उनके पास अपने ऋण दायित्वों को कवर करने के लिये अधिक पर्योज्य आय (Disposable Income) है।
- हाल की अवधि इन दोनों चर (DTI और ब्याज भुगतान) में तीव्र वृद्धि से संबंधित है।
- परिवारों का ऋण-आय अनुपात दो कारकों के कारण परिवर्तित हो सकता है।
 - उच्च शुद्ध उधार-आय अनुपात, जहाँ कुल उधार और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
 - यदि परिवार उच्च नविश या उपभोग के वित्तपोषण को बढ़ाने का नरिणय लेता है।
 - ब्याज दरों में वृद्धि नाममात्र आय (Nominal Income) वृद्धि दर में कमी।
 - यदि ब्याज भुगतान में वृद्धि आय वृद्धि से अधिक है, तो ऋण-आय अनुपात बढ़ता रहेगा। ऐसे तंत्रों को "फिशर डायनेमिक्स" (ब्याज दर और नाममात्र आय वृद्धि दर में परिवर्तन के संदर्भ में बढ़ते ऋण-आय अनुपात की घटना) के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- घरेलू आय वृद्धि उधार दर से पीछे:
 - 2019-20 से 2022-23 की अवधि के लिये घरेलू पर्योज्य आय की वृद्धि दर का औसत मूल्य (2019-20 से 2021-22 में 8% और 2019-20 से 2022-23 में 9.3%) भारति औसत उधार दर (Weighted Average Lending Rate- WALR) (2019-22 में 9.3% और वर्ष 2019-23 में 9.4%) से कम रहा है।
 - इस अवधि के लिये उधार दर का औसत मूल्य भारतीय रज़िर्व बैंक के तमिाही आँकड़ों द्वारा तय किया गया है।

Lending rate and the household GDI growth (%)		
	2019-20 to 2021-22	2019-20 to 2022-23
Avg. lending rate (RBI)	9.3	9.4
Average household GDI [^] growth rate	8.0	9.3
Average household GDI growth rate minus Average WALR*	-1.3	-0.1

■ 2003-08 और 2019-22 के बीच बचत और नविश में गरिावट:

- वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक औसत सकल राष्ट्रीय आय (Gross National Income- GNI) वृद्धि दर (14.5%) औसत उधार दर (11.5%) से अधिक थी।
 - इसका तात्पर्य यह था कि आय उधार लेने की लागत की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही थी।

Lending rate and the GNI growth (%)		
	2003-04 to 2007-08	2019-20 to 2021-22
Average Lending rate (IMF)	11.8	8.8
Average GNI** growth rate	14.5	8.7
Average GNI growth rate minus Avg lending rate	2.7	-0.1

■ फिशर डायनेमिक्स 2019-20 से सकरयि है:

- यह ब्याज दर और नाममात्र आय में परिवर्तन के कारण ऋण-आय अनुपात बढ़ने की घटना है।
- वर्ष 2019-20 में आर्थिक मंदी के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने फिशर डायनेमिक्स के संकेत दिखाए हैं।

- **कोविड-19** के बाद, परिवारों की आय की तुलना में ऋण की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण नाममात्र (Nominal) की आय वृद्धि दर है।
- मछुआरों की गतिशीलता के उदय के साथ, **भारतीय अर्थव्यवस्था के समकक्ष 2 महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:**
 - **बढ़ता आय-ऋण अंतर:** इससे परिवारों को अधिक ब्याज भुगतान करना पड़ सकता है।
 - **न्यूनतम खपत:** अधिक ऋण परिवारों को खर्च में कटौती करने के लिये प्रेरित करता है। वर्ष 2023-24 में खपत और GDP अनुपात में गतिवट आई, जो इस प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

बढ़ते घरेलू ऋण बोझ के व्यापक आर्थिक नहितार्थ क्या हैं?

- **ऋण अदायगी:** यदि आय वृद्धि की तुलना में ब्याज दरें तेजी से बढ़ती हैं तो यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है इससे वित्तीय क्षेत्र पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि उन्हें ऋण अदायगी के लिये संघर्ष कर रहे परिवारों से न्यूनतम ब्याज आय प्राप्त होती है। इसके परिणामस्वरूप व्यवसायों के लिये ऋण उपलब्धता कम हो सकती है।
- **उपभोग मांग:** इसे उच्च घरेलू ऋण द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। यदि परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे अधिक बचत कर सकते हैं और खर्च में कमी कर सकते हैं, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी।
- **मुद्रास्फीति से बचाव हेतु उच्च ब्याज दर:** यदि मुद्रास्फीति से निपटने के लिये ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं, तो इससे घरेलू ऋण का बोझ बढ़ सकता है और वे ऋण जाल से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा इसलिये होगा क्योंकि उच्च ब्याज दरें होने से परिवारों द्वारा अपने ऋणों के लिये भुगतान की जाने वाली धनराशि में वृद्धि होगी।
- **अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण:** घरेलू बैलेंस शीट में वित्तीय परसिंपत्तियों की ओर बदलाव से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था अधिक वित्तीय होती जा रही है। इसका तात्पर्य है कि आर्थिक गतिविधियाँ एक बड़ा हिससा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बजाय वित्तीय बाजारों पर केंद्रित हैं। यह अर्थव्यवस्था को अधिक नाजुक और वित्तीय संकटों के लिये प्रवण बना सकता है।
 - वित्तीयकरण उन अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है जहाँ वित्तीय बाजार उत्पादन पर प्राथमिकता लेते हैं, जहाँ व्यक्ति धन संचय करने के लिये स्टॉक और बॉण्ड जैसी वित्तीय संपत्तियों की ओर रुख करते हैं।

आगे की राह

- **आय वृद्धि और ऋण नियंत्रण पर ध्यान देना:** ब्याज दरों और आय वृद्धि के बीच अंतर को कम करने की आवश्यकता है और आय की तुलना में घरेलू ऋण की वृद्धि को धीमा करने की आवश्यकता है।
- **आय वृद्धि को बढ़ावा देना:** रोजगार सृजन, वेतन वृद्धि और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ एवं पहल महत्त्वपूर्ण हैं।
- **ऋण स्तर का प्रबंधन:** उचित ऋण प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और संभावित रूप से अत्यधिक उच्च ऋण दरों को वनियमित करने से, परिवारों को ऋण को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता मिल सकती है।
- **वेतन वृद्धि:** यदि वेतन में वृद्धि, ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि से अधिक है, तो परिवारों के पास ऋण का प्रबंधन करने और संभावित रूप से अधिक खर्च करने के लिये अधिक प्रयोज्य आय होगी।
- **ऋण प्रबंधन रणनीतियाँ:** वित्तीय शिक्षा पहल और उचित ऋण देने की प्रथाएँ परिवारों को ऋण को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता कर सकती हैं, जिससे खर्च के लिये कुछ आय शेष रह जाती है।

दृष्टि मनेस प्रश्न:

भारत की घरेलू वित्तीय संपत्तियों में गतिवट और उधार लेने की बढ़ती लागत पर चर्चा कीजिये। इस प्रवृत्तियों से उत्पन्न होने वाली संभावित व्यापक आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और उनसे निपटने हेतु नीतिगत उपाय प्रस्तावित कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित "कृषक-कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण" के अनुसार नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये: (2018)

1. राजस्थान में ग्रामीण कुटुम्बों में कृषक कुटुम्बों का प्रतशित सर्वाधिक है।
2. देश के कुल कृषक कुटुम्बों में 60% से कुछ अधिक ओ.बी.सी. के हैं।
3. केरल में 60% से कुछ अधिक कृषक कुटुम्बों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 2 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: c

प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि(2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है,
- (b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
- (c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है,
- (d) सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है,

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rising-debt-strained-household-savings>

